Keynote Address at Zee Business Ministerial Conclave

29.09.2016 | New Delhi

बहुत बहुत धन्यवाद! Zee Business का खास तौर से मैं शौकीन इसलिए हूँ कि व्यापार की दुनिया में हिंदी-भाषी शायद ये सबसे पहला चैनल था जिसने वास्तव में पूरे भारत को जोड़ा Business के साथ, नहीं तो वही अंग्रेजी channels के माध्यम से एक सीमित television audience तक business की बातें पहुँचती थी ! इसलिए सबसे पहले तो सुभाष जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा कि वो अपना चैनल ही नहीं बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं पर इस प्रकार के गोष्ठियों से नए विचार भी देश की जनता तक पहुंचाते हैं ! आज का जो subject आपने infrastructure के ऊपर discussion रखी है, infrastructure के कई पहलू आज discuss हुए हैं, मेरे पहले अभी steel और tourism की बात हो रही थी, उसके पहले शायद railways की बात की है आप लोगों ने ! और उसी कड़ी में बिजली का भी क्षेत्र काफी अहम् भूमिका निभाता है ! उलटे एक मैं किधर पढ़ रहा था 'Electricity is also like the people's railway, जितना ज़रूरी रेलवे रहती है आज एक भारत की जीवन प्रणाली में रेलवेज का जो स्थान है उसी प्रकार से मुझे लगता है बिजली भी हम सब के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है कि हम सबके घरों में बिजली पहुंचे, घरों में बिजली चौबीसों घंटे रहे, बिजली के दाम कम रहे जिससे सभी लोग उसको अफ्फोर्ड कर सकें ! और इस सरकार ने लगभग पहले दिन से ही ठान लिया था कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कैसे चौबीसों घंटे बिजली हर घर को मिले, उद्योग और व्यापर को भी पर्याप्त मात्रा में जितनी बिजली चाहिए पूरी मिले, किसानों को पूरी बिजली मिले जितनी उनकी ज़रुरत है उसके हिसाब से और मैं समझता हूँ एक परिस्थिति देश में पहली बार निर्माण हुई है जब भारत Power-surplus country बना है !

अभी तक की हमारी जितनी policies थी और कई बार आज कल भी मेरे पास कोई policy document आता है तो मैं देखता हूँ कि mindset अभी भी वो shortages का mindset है कि हम बिजली इतनी allocate करेंगे, इतनी allot करेंगे, इस प्रकार से उसका end-use restriction लगाएंगे ! अभी तक शायद जो पूरी व्यवस्था है bureaucracy बोलो या जो सरकारी व्यवस्था है और शायद कुछ मात्रा में देश के लोग भी अभी तक अपने मन में ये ग्रहण नहीं कर पाए हैं कि today India is a power-surplus country. May be it will take some time but I can assure the people of India आप लोगों के माध्यम से कि अब भारत में पर्याप्त बिजली उत्पादन करने की क्षमता है ! आज की requirement के लिए नहीं, आने वाले कई वर्षों की requirement की क्षमता आज उपलब्ध है जिस प्रकार से plans किए गए हैं और projects दिनों दिन लगते रहेंगे, renewable energy, नवीकरणीय ऊर्जा को एक तेज़ी से गति दी जा रही है, उससे capacity, उससे generation बढेगी, आगे चलके जल्दी UMPPs bid out होने जा रहे हैं, इन सबको अगर एक कड़ी में जोडें तो मुझे लगता है आज भारत में इतनी क्षमता है कि हम अपनी power generation को double कर सकते हैं और देश में कोई भी व्यक्ति को, कोई भी उद्योग को, किसी को भी कभी बिजली की कमी न हो इतनी हमारे में ताक़त है, इतनी इस देश में क्षमता है ! उलटे शायद पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले ही मैंने Chief of Army Staff से भी बात की थी कि जितने Border areas हैं वहां पे हमें मदद दीजिए कि हम वहां पे एक transmission line और grid बिछा सकें कि वहां के लोगों को, villages को भी बिजली मिले और आर्मी को भी सुविधा मिले अपनी पेट्रोलिंग के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए ! और मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि कितना संजोग है कि शायद हफ्ता या 8-9 दिन पहले ही मेरी जनरल सुहाग के साथ बात हो रही थी इस विषय में और आज हम सब गर्व के साथ देख रहे हैं

कैसे भारत की सेनाओं ने भारत के गर्व, हम सब को गौरन्वित किया है, हम सबको सुरक्षित महसूस करने का एक और, अपना ताक़तवर प्रदर्शन करके हम सबको दिखाया है ! और इस के लिए मैं समझता हूँ हम सबकी तरफ से भारत की सेना को, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को एक ज़ोरदार तालियों से उनका अभिनन्दन किया जाए ! अब जो परिस्थिति निर्माण हुई है अब उसमें हमें देश के लोगों को बिजली या ऊर्जा कैसे और अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने के मौके दिए जाए उसपे गौर करने की आवश्यकता है परसों ही हम एक चर्चा कर रहे थे उसमें ये निकला कि electric vehicles, बिजली से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं आज पूरा विश्व देख रहा है कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, greenhouses gases को कम किया जाए और उसमें petroleum utilization से जो pollution होता है उसका एक replacement gradually विश्व में electric vehicles से किया जा रहा है ऐसे में जो western developed countries हैं उनको तो अपनी जो existing car base है, automobile base है उसको replace करना पड़ेगा with electric mobility or electric vehicles. तो पहले जो petroleum-driven cars हैं उसको scrap करके they will have to convert them to or buy new electric vehicles. भारत अभी भी एक emerging economy है, developing country है, अभी भी इस देश में बड़ी बड़ी मात्रा में लोग नई गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग जैसे जैसे incomes rise होती हैं वैसे वैसे पहले शायद two-wheeler खरीदना चाहते हैं आगे चलके four-wheeler खरीदते हैं, और संपत्ति आती है तो और अच्छी सुन्दर sedan या कुछ खरीदते हैं, SUV खरीदते हैं ! तो भारत में ये श्रंखला अब शुरू ही हुई है we will be needing millions of new cars going forward. तो मैं समझता हूँ भारत को leapfrog करना चाहिए technology के साथ, rather than पहले हम petroleum-driven vehicles देश में introduce करें और जब दुनिया में सब लोग electric हो जाएं तब हम जा के अपनी गाड़ियाँ replace करें. भारत को सोचना पड़ेगा कैसे हम शुरू में ही electric vehicles का जाल बिछा सकें, ऐसा infrastructure create करें कि देश-भर में electric vehicles becomes the norm rather than the exception.

और मुझे आप सबको बताते हुए ख़ुशी होती है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पे बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं. आनंद गीते जी की ministry, Heavy Industries Ministry इसपे काम कर रही है और हम सब मंत्री नितिन गडकरी जी, धर्मेन्द्र प्रधान, Environment Minister अनिल माधव धवेजी, मैं, हम सब मिलके उसमें सहयोग दे रहे हैं कि कैसे आगे आने वाले दिनों में भारत एक electric vehicles की तरफ और तेज़ी से जाए, इस प्रकार के नए नए आयाम भारत में जितना हम introduce कर सकते हैं उतना ज्यादा आगे भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, नई technologies से लोगों को लाभ मिलेगा और अभी अभी 2 अक्टूबर को जो हम पेरिस में करार किया था उस करार को 2 अक्टूबर को भारत ratify करने जा रहा है, कल ही कैबिनेट में उसका approval हुआ है और 2 तरीक को हम वो document New York में पेश करने जा रहे हैं, UN में! तो मैं समझता हूँ एक अच्छा संकेत है कि आज के दिन Zee Business Ministerial Conclave building India की बात कर रहा है, आज ही के दिन खुशखबरी मिली है about Protecting India और 2 तरीक को the future of India will be determined, a more clean future, a brighter future, a more environmentally-friendly future and a more sustainable future.

मैं आप सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ आज के इस बहुत महत्वपूर्ण दिन पे Zee Business Ministerial Conclave हुआ है और आगे चलके मुझे पूरा विश्वास है कि Zee Business लगातार लोगों की भी सेवा करता रहेगा, लगातार व्यापार और जनता को जोड़ता रहेगा और साथ ही साथ देशभक्ति, a true spirit of

nationalism जो मैंने Zee के हर एक चैनल में देखा है उस spirit को जनता तक पहुंचा के भारत को और मज़बूत बना देगा! बहुत बहुत धन्यवाद!

Moderator: आज दोपहर में मेरी दरअसल पीयूष जी से बात हुई थी, वो उस समय वहीँ पर थे जिस राज्य से आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे पास आई है कि जहाँ पर LOC पर भारत ने सैन्य कार्यवाई करके जो आतंकवादी कैंप हैं उन्हें नष्ट किया, जम्मू कश्मीर में थे आज, और दोपहर में जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तब उन्होंने भी कहा कि आज Ministerial Conclave के लिए बहुत अच्छा दिन मिल गया है आप सबको, मेरी वाकई आने की ज़रुरत है मैंने कहा सर अब तो बिलकुल है ! फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम में काफी कुछ बदलाव किया, एक-आद फ्लाइट मिस की और दूसरी पकड़ी और यहाँ पे आए तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका ! लेकिन आपने जो बात कही मैं उसी से शुरुआत भी करना चाहूँगा and then obviously we will discuss about Power and Coal. एक कहावत है हिंदी में कि कुछ लोग इशारों में समझ जाते हैं, कुछ लोग बातों से समझते हैं और कुछ लोग लातों से समझते हैं ! तो क्या ये माना जाए कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने ये सन्देश न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर को दिया है कि अगर आप हमारी बातें नहीं समझते हैं तो हमें बातें समझाने के और तरीके भी आते हैं !

Hon'ble Minister: मैं समझता हूँ अगर किसी ने इस बात को पहले नहीं समझा तो वो मूर्खता थी ! प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सन्देश लगभग सभी लोग पहले से समझते हैं कि ये एक देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेंगे और भारत की जनता इनके नेतृत्व में अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करती है और मैं समझता हूँ जिस तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है और जिस रट आत्मविश्वास से आज हम सब भारतवासी लगे हुए हैं अपने अपने काम में और उसमें सेना भी अपना काम कर रही है ! मुझे लगता है किसी को कोई भारत के ऊपर आंच भी डालने की कोई हिम्मत नहीं हो सकती !

Moderator: यानी जब जब इस भाषा में बात होगी जवाब भी इसी भाषा में दिया जाएगा !

Hon'ble Minister: वो तो काफी whatsapp पे messages घूम रहे हैं जिसमें प्रधान मंत्री जी के पुराने भाषणों का भी उल्लेख होता है जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट ये बात बताई थी कि भारत की सीमाओं के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता है और भारत में इतनी क्षमता है, इतनी ताक़त है कि nobody can take us for granted.

Moderator: बिलकुल, लेकिन चलिए पीयूष जी क्यूंकि आप आज ही जम्मू कश्मीर से लौटे हैं मैं उसी से शुरुआत भी करना चाहूँगा क्यूंकि आपने खुद जैसे अपने वक्तव्य में भी कहा ये जो इलाके हैं देश के चाहे वो उत्तर पूर्वी भारत हो या फिर जम्मू कश्मीर हो यहाँ पर क्यूंकि बाकी जो strategic challenges हैं भारत के सामने वो तो हैं ही लेकिन साथ ही एक बहुत ही बुनयादी जो challenge है वो यही है कि वहां पर पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, सड़क पहुंचे जिससे वो इलाके देश के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएं ! इस पर आपका vision क्या है आने वाले समय के लिए?

Hon'ble Minister: उलटे आज जो मैं जम्मू कश्मीर में था उसमें भी आज हम सलाल hydro power project पे थे तो आज जो पूरा focus of discussion था मैं आपके साथ share कर सकता हूँ उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि क्या परिवर्तन हुआ है पुरानी सोच में और नई सोच में ! उदाहरण के लिए, इस प्रोजेक्ट का जो reservoir है ये 22 km का reservoir था अब मात्र 2 km का रह गया है 22 बनाम 2, सालों साल से silting हो रही है कभी किसी ने चिंता नहीं की ! और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मुझे भी ये बात दो वर्ष से मैं मंत्री हूँ मेरे तरफ पहुंची नहीं थी तो जैसे ही ये पता चला तो, of course, उसके लिए तो मैंने कहा ही कि तुरंत roadmap बनाइए कैसे उसको

dredging करें, not temporarily एक permanent dredging की क्या व्यवस्था हो सकती है ! पिछले, दो हफ्ते पहले मैं नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ एक पॉवर प्रोजेक्ट में हिमाचल गया था वहां पे हमने देखे थे कैसे वो पानी आता है और साथ की साथ de-silting होती है, साफ़ पानी पॉवर प्लांट में जाता है और वो जी silt निकलती है अलग पाइप से साइड से निकालके फिर रिवर में डाली जाती है ! मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ अच्छा भला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ लेकिन वो ध्यान में था तो मैंने कहा यहाँ भी कुछ, they said this will not work here, I said maybe this will not work something else will work here. पर साथ ही साथ ये जैसे ही ध्यान में आया तो एक तरीके से इसका root cause analysis बाकी देश के 50 और hydro power projects में भी किया जाए ये भी साथ में ध्यान आ गया! तो निर्देश दो दिए गए सलाल में क्या करना है वो roadmap बनाइए और immediately NHPC के जो 20 और HPPs हैं और फिर that same instruction will go for all other projects. That is the difference in the thinking in the past and now. दूसरा, ये प्रोजेक्ट 30 साल पुराना है तो मैंने पूछा नई technologies कुछ आई हो, कैसे हम इस प्रोजेक्ट की capacity enhance कर सकते हैं, एक existing infrastructure है, can we replace the power turbines to generate more electricity? can we add a turbine within the existing infrastructure? आखिर आज land acquisition problems हैं, environment problems कई प्रकार के समस्याएं आती हैं नए प्रोजेक्ट में तो क्या हम सोच सकते हैं कि देश में existing projects को expand करके और after all ये बिजली घर की बिजली 94 पैसे में बनती है, 94 paisa per unit, उसमें सवा रूपए state के water cess add होते हैं उसके बावजूद 2.12 पैसे या कितने में जाता हैं, इतनी अच्छी, इतने अच्छे कम कीमत पे बिजली जहाँ बनती हो वहां अगर उत्पादन बढ़ता है तो वो वहां के लोगों को सेवा ही कर पाएगा ! तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से जो दूर दराके के इलाके हैं, particularly the strategic states, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल है, नार्थ ईस्ट में जायें तो अरुणाचल, सिक्किम बाकी हमारी seven sisters, असम वो पूरा इलाका, मुझे लगता है इन सब इलाकों पे focused attention देके, वहां हर घर को बिजली मिले, पानी घरों तक पहुंचे, खास तौर पे पहाड़ों पे ! आज जैसे मैं जिस रिआसी डिस्ट्रिक्ट में था उस जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जब रिव्यु हुआ तो उन्होंने बताया कि 56,000 घर हैं, 26,000 घरों में अभी तक बिजली नहीं गयी है, 5,000 घरों के लिए उनके पास existing schemes में provision है तो मैंने थोड़ी back of the envelope calculate करके देखा, लगभग 63 करोड़ रूपए और मिल जाए तो बाकी 21,000 घरों में भी बिजली जा सकती है ! So I have told him to sit with my officials in Delhi और 2 साल के भीतर वह बाकी 21,000 भी बिजली से लाभान्वित हो जाएं उसकी scheme बनाने को आज निर्देश देंगे!

Moderator: बिलकुल, गोयल जी जो एक दूसरा सवाल है और ये सवाल मैं आपको हमारे जो दर्शक हैं जोकि सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क के सबसे ज्यादा दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ ! उनको अक्सर एक सवाल सताता है कि एक तरफ जब वो न्यूज़ चैनल्स में, अख़बारों में सुर्खियाँ पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर पढ़ते हैं कि भारत एक power-surplus nation है, देश में अब पॉवर की कमी नहीं है, हो सकता है उसके transportation में या grids में issues हों ! और दूसरी तरफ देश के कई इलाके ऐसे हैं आप मुंबई से हैं, मैं भी मुंबई से हूँ तो वहां तो कभी बिजली जाती नहीं है लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली कभी आती नहीं है ! तो ये जो जिससे हम विसंगति कहते हैं, एक तरफ surplus nation और दूसरी तरफ the dark spots in the country, इससे कैसे आपकी ministry address करेगी?

Hon'ble Minister: देखिए ये संघीय ढांचा है भारत का बिजली का क्षेत्र, केंद्र में बैठके हम पॉलिसीस बना सकते हैं, अच्छे स्कीम्स बना सकते हैं लेकिन end में distribution companies जो अधिकांश state-owned हैं उन्हें बिजली खरीद् के last mile distribution consumer तक पहुंचानी पड़ेगी ! और उसमें केंद्र की तरफ से हम, I cannot force the power down their throat; the states will have to buy the power. तो इसके ऊपर मैंने काफी विचार करने के बाद, of course, एक तरफ तो हमने UDAY scheme, Ujwal Discom Assurance Yojana से ये discoms को और सुद्रिड बनाना, इनको और मज़बूत बनाने के पूरा योजना तो बनायी है साथ ही साथ मैंने transparency को और technology का इस्तेमाल करके information जनता को पहुँचाने की कोशिश की है ! तो अब हमारा एक विद्युत् प्रवाह मोबाइल एप्प है जिसके माध्यम से जनता तक जानकारी मिलती है कि हर वक़्त, any time of the day, 24 hours, कितनी बिजली power exchange में भी उपलब्ध है, वैसे तो अधिकांश states के पास power purchase agreements ही enough है पर उसके इलावा power exchange में भी पर्याप्त मात्रा में बिजली चौबीसों घंटे available होती है! राज्य सरकारें खरीदें और जनता को दें उसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोग और आपके चैनल इसको इस्तेमाल करके जनता तक ये जानकारियाँ पहुंचाएं तो मैं समझता हूँ आप भी देशहित का काम करेंगे कि कैसे जनता को पता चले ! आज नॉएडा में, यहाँ पे कुछ लोग होंगे ज़रूर जो नॉएडा में रहते होंगे और मुझे बताया जाता है नॉएडा में अभी भी पॉवर कट्स होते हैं ! तो आप विद्युत् प्रवाह अभी खोलिए उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने दाम पे इस वक़्त यूपी सरकार खरीद सकती है बिजली, आपको दिख जाएगा कि यूपी सरकार ने कितनी power shortage declare की है और ये दिख जाएगा कि कितनी बिजली वो खरीदी है उन्होंने आज ! और ज्यादा करके अधिकांश दिन में देखते रहता हूँ वो दिखाते हैं कि zero shortage and zero power purchase. अगर zero shortage है तो नॉएडा में बिजली जानी ही नहीं चाहिए फिर तो सबको चौबीस घंटे बिजली मिलनी चाहिए !

Moderator: आप बार बार यूपी का नाम ले रहे हैं, ये क्या कोई संकेत है?

Hon'ble Minister: नहीं क्यूंकि यूपी हमारे neighbourhood में है और ज्यादा मुझे बताया गया है कि जो journalists हैं दिल्ली के वो अधिकांश मयूर विहार वगैरा से आगे नॉएडा में रहते हैं ! इसलिए मैं बार बार यूपी का जिकर करता हूँ आप कहें तो बिहार का जिक्र कर लेते हैं, आप कहें तो और कहीं का जिक्र कर लेते हैं!

Moderator: सर दूसरा एक इशू है, हाल ही में और मैं कोई विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन, एक उदहारण के तौर पे अगर हम नगला फटेला की बात करें या फिर क्या इस परिभाषा को बदलने की ज़रुरत है कि बिजली की तार पहुंचना और उस बिजली की तार में वाकई बिजली पहुंचना, ये जो electrification की व्याख्या है उससे बदलने की ज़रुरत है, definition को?

Hon'ble Minister: देखिए definition बदले नहीं बदले उससे कुछ फर्क़ नहीं पड़ने वाला है ultimately आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है ! केंद्र सरकार जैसे मैंने पहले बताया हम पालिसी बनाते हैं, हम पैसा देते हैं राज्य सरकारों को, मेरे पास 300 लोग हैं बिजली विभाग में पूरे केंद्र सरकार में और वो जाके लाखों villages में आज काम चल रहा है देश भर में, intensive electrification जिसमें हर घर तक बिजली पहुंचे ये काम देश में लाखों villages में चल रहा है ! Village तो revenue village, जब hamlets और तोले धानी वगैरा लें तो maybe 4-5 लाख hamlets में काम चल रहा होगा ! ऐसी परिस्थिति में मुझे राज्य सरकार के ऊपर ही निर्भर

होना पड़ेगा और जो राज्य सरकार मुझे कुछ रिपोर्ट देती है मुझे उसपे विश्वास करना पड़ेगा, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई राज्य सरकार को चाहे वो मेरी पार्टी की हो या कोई और विपक्षीय पार्टी की हो सभी आखिर अधिकारी काम कर रहे हैं वह सब एक प्रकार से government servants, public servants काम कर रहे हैं ! जो राजनीतिक नेता चुन के गए हैं वो भी public servants हैं जनता ने चुन के भेजे हैं तो मैं तो विश्वास करता हूँ कि जब मुझे कोई रिपोर्ट मिलती है तो I have to trust it and I have to declare it. तो नगला फटला का आपने अच्छा example लिया मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत सेवा करी कि उन्होंने 10,070 गावों में से उस दिन नगला फटला को चुना ! मुझे तो पता नहीं था कोन सा चुनेंगे, मेरे तो गर्व एप्प में हर गाँव की डिटेल दे रखी है क्या क्या Electrify हुआ है उसमें उन्होंने शायद आगरा नजदीक है मथुरा, तो उस इलाके का नगला फटला चुन लिया कि ये देखो दिल्ली से इतना नजदीक बिजली नहीं थी ! और फिर जब उन्होंने announce किया तो मालूम पड़ा कि बिजली की तारें तो लगीं, बिजली की व्यवस्था लगी, transformer भी energise हुआ क्यूंकि मेरे पास रिपोर्ट है 24 नवम्बर, 2015, को पूरी व्यवस्था बिजली की पहुँचने के बाद राज्य सरकार के पांच-पांच अधिकारियों ने sign करी हुई रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पे transformer energise हो गया, पूरी line diagram दी, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, पत्रकारों से, line diagram के साथ उन्होंने बताया इस इस घर में बिजली पहुंची है ! लेकिन 24 नवम्बर, 2015 के बाद बिजली actually उन लाइनों में नहीं थी, अब मुझे यहाँ दिल्ली में, अच्छा मैंने इसको transparently गर्व में जनता को बता दिया कि नगला फटला अब एलेक्ट्रिफय हो गया है! मैं चाहता हूँ आप मीडिया के लोग इस बात को देश भर में, अलग अलग राज्यों में इसको ज़रा प्रचारित करें कि देखिए आप के राज्य में इन सब गावों में बिजली पहुंची ऐसा state government ने दावा करके केंद्र से पैसे लिए हैं इस काम के लिए ! तो अगर किसी को नहीं मिली हो तो ज़रा हल्ला मचाइए ! ये people-driven movement होना पड़ेगा !

Moderator: बिलकुल, I think ये बहुत बड़ी बात कही आपने!

Hon'ble Minister: और नगला फटला की मजेदार बात देखिए कि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ये बात छेडी कि वहां पे बिजली पहली बार पहुंची है तब राज्य सरकार के अधिकारी ऐसे भागे कि दोपहर को चार बजे तक फिर बिजली भी आ गई वहां पे !

Moderator: आपने Paris Climate deal की बात की और ये भारत की तरफ से बहुत बड़ा कदम अपने आप में है, अब इसमें जो प्रदूषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो thermal power capacity है भारत की और ज़रुरत भी है वो काफी ज्यादा है अब जैसे ये डील आगे बढ़ेगी हमें alternate जो power या फिर energy production की technologies उसपे जिस पर आपकी सरकार काफी काम कर रही है आप खुद भी काफी काम कर रहे हैं! इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा ! इसका roadmap क्या होगा और इसमें challenges क्या हैं?

Hon'ble Minister: देखिए challenges तो मुझे कोई दिखते नहीं हैं पर विशेष, पर opportunities ज़रूर बहुत दिख रही हैं इसमें, संभावनाएं बहुत हैं ! खास-तौर पे जहाँ तक thermal plants की बात है देखिए thermal plants तो भारत में रहेंगे ! After all you need a base load, अगर यहाँ कोई technical आदमी होगा आपके audience में तो आपको बताएगा कि अगर base load नहीं हो तो आखिर दो समस्याएं हैं, renewable energy डाल ही नहीं सकते हो grid में जब तक एक base load नहीं है - Point 1, और Point 2 अगर thermal plants नहीं चलते हों तो आपको Zee Ministerial Conclave 4 बजे के पहले

खत्म कर लेना पड़ेगा, क्यूंकि ये सब बिजली बंद हो जाएगी ! After 5.36 in the evening India will go back to the stone age, हम सब candle light dinner करेंगे, maybe it will be more romantic but we will not have the privilege of getting 24/7 power. तो ये एक combined effort होता है, thermal plants अपनी जगह बहुत ही महत्व रखते हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ये thermal plants बहुत ज़रूरी है क्यूंकि कोयला हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ! तो ये तो मेसेज बहुत क्लियर है और मैंने विश्व के सभी लोगों को बहुत क्लियर मेसेज दिया है कि हमारे कोयले के प्लांट्स चलेंगे और हम expand भी करेंगे लेकिन कोयले को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, super-critical plants अधिकांश लगाना, पुराने inefficient plants को replace करना with more better quality plants, कोयले को wash करके use करना; इस सब चीजों पे ज़रूर भारत बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा जिससे ये कोयले के प्लांट्स भी बिना प्रदूषण के चले! अब मैं पीछे जापान गया था योकोहामा में, शहर के बीचमबीच एक थर्मल प्लांट है लेकिन रत्तीभर पता नहीं चलता है कि यहाँ थर्मल प्लांट है ! तो नई technologies का इस्तेमाल अब भी भारत भी तेज़ी से करेगा, हमने compulsory कर दिया कि आगे जो भी प्लांट लगेंगे वो super-critical और better, ultra super-critical. साथ ही साथ renewable energy का जो भारत का लक्ष्य है वो unparalleled है विश्व के इतिहास में, इतना fast ramp-up विश्व का कोई देश नहीं कर रहा है जितना भारत आगे करने जा रहा है ! तो मुझे पूरा विश्वास है thermal, renewable और एक आगे चल के जैसे जैसे technology advancement होगी तो शायद storage भी सस्ता हो जाएगा और storage सस्ता होने से renewable energy को और गति मिलेगी और बल मिलेगा ! तो ये सब co-exist करेंगे और एक roadmap पूरा बनाया गया है कैसे इन सबको co-exist भी कराना, साथ ही साथ demand side management, energy efficiency पे हम बहुत बल दे रहे हैं कि कैसे wasteful energy न use हो ! एक मात्र हमारा LED roll-out program भारत के consumers का और आप सबका Rs 40,000 करोड़ रूपए सालाना बिल में बचत करेगा, जनता के, just one LED program.

Moderator: Before I throw the floor open, मैं बस एक आखरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और ये सवाल से ज्यादा शायद आपके vision को लेकर मेरा प्रश्न है ! आज Zee Business के इस Ministerial Conclave के मंच से क्या आप देश को एक समय-सीमा दे सकते हैं जब भारत हकीकत में एक power cut-free nation होगा?

Hon'ble Minister: मैं समझता हूँ अधिकांश भारत तो अगले दो-ढाई-तीन वर्ष के अन्दर power cut-free हो सकता है, हाँ of course, कुछ states को मौका मिलेगा आने वाले दिनों में कि वो एक सरकार लाएं जो इस काम को करने में सक्षम हो तो. इसलिए लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, अगर लोग ही नहीं पसंद करें कि उनको 24/7 बिजली मिले, किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, उद्योगों को चौबीस घंटे बिजली मिले, तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं केंद्र में बैठके ज़बरदस्ती राज्यों को थोप नहीं सकता हूँ ! लेकिन इतना आपको पक्का विश्वास दिला सकता हूँ, केंद्र चार कदम आगे बढेगा अगर राज्य एक कदम भी आगे बढे जिससे कि अगले आने वाले ढाई-तीन वर्षों में हमने लक्ष्य 2022 का रखा था पर अब मुझे लगता है हम 2019 ही ऐसी व्यवस्था create कर सकते हैं कि इस देश में power cut-free तो क्या, on the contrary आपके पास कटोरा लेके पॉवर बेचने के लिए लोग आने चाहिए कि साहब आप थोड़ी बिजली अधिक खरीद्लो, ये हालत होनी चाहिए देश में !

Moderator: That's a telling statement, और मैं अगली बार जब आपसे मुलाक़ात होगी तब हम इसका reality check लेंगे, but I will throw the floor open……

Hon'ble Minister: As I said subject to the state governments cooperating in that, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो, मैंने पीछे एक आंकड़े निकाले थे, एक राज्य है हमारे पडोसी राज्य है यहाँ से, पडोसी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे कूटनीति में भी देश का नाम नहीं लेते पर पडोसी देश बोलते हैं, वैसे यहाँ पे एक पडौसी राज्य है जहाँ केंद्र सरकार ने लगभग Rs 11,000 करोड़ मेरे आने के पहले और मेरे आने के बाद Rs 7,000; Rs 18,000 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिया था लेकिन मैं पिछले 5-7-8 वर्षों का आंकड़ा निकाल रहा था कुछ काम ही नहीं हुआ ग्रामीण विद्युतीकरण का ! हमारे आने के बाद मोदी जी ने जब धक्का लगाया कि भारत के पूर्वी इलाकों को प्रगति होनी चाहिए, तब धक्का लगा के काम किया उसके बावजूद नगला फटला जैसे incidents हुए ! तो मैं समझता हूँ कि जनता को भी जागृत होना पड़ेगा कि एक अच्छी सरकार आए, और अच्छी सरकार जो जनता की सेवा में लगे बजाए कि आपसी पारिवारिक झगड़ों में पड़ी रहे!

Moderator: बिलकुल, now I will throw the floor open, can we have the mikes please? Quickly, we will take some questions.

Q. I am professor Rakesh Mohan Joshi, incidentally 7-8 years back I wrote a case study which was awarded by London Business School on rural electrification of Gujarat on that Gram Jyoti Yojana, now this Gram Jyoti Yojana you know the biggest thing which I think you are aware of that, you know, India is the country with the highest number of people who lives without electricity. Now India, you know, we claim that we are electricity-surplus but on the ground reality is we have a serious problem in, you know, transmission and distribution losses in this country which is highest on the earth, among them. The second thing is, you know, within the states there is a variation that we fully agree with you, could be from 40% to maybe 10% at the best. So under the given situation of the central government and the federal states where different political parties are there so there are two things, one is the political management of the states where, you know, the power is between the different political parties. And the second thing is, using technological innovations for leapfrogging the technology, you know, to make this distribution possible into the small hamlets and the islands and, you know, the villages and dhanis and all sorts of things.

Hon'ble Minister: आप सबको जानके ये ख़ुशी होगी कि संघीय ढांचा होने के बावजूद और अलग अलग political ideologies की सरकारें होने के बावजूद UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana), जो एक voluntary scheme थी इसमें कोई हमने ज़बरदस्ती कोई राज्य को ज्वाइन करने को नहीं कहा लेकिन लगभग पूरे देश के सभी राज्य उसमें जुड़ चुके हैं ! दो-तीन बड़े राज्य बाकी हैं वो भी मुझे लगता है महिना-डेढ़ महीने में वो भी जुड़ जाएंगे ! तो ये एक demonstration होगा कैसे मोदी सरकार ऐसी योजनाएं लाती हैं जो देश-हित में होती हैं,

जनता के हित में होती हैं कि हर एक पोलिटिकल पार्टी की राज्य सरकार भी उसमें जुड़ने को उत्सुक रहती है ! मैं बिहार का चुनाव हारा, भारतीय जनता पार्टी हारी लेकिन उसके 15-20 दिन के अन्दर वहां की राज्य सरकार ने कहा हमें उदय join करना है ! उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो हमारे साथ ताल-मेल नहीं रखती है लेकिन that was amongst the first states to join UDAY, तो मैं समझता हूँ अगर नीतियां अच्छी हों, इमानदारी से हम देश के समक्ष अच्छा काम करने जाएं तो संघीय ढांचे में भी काम हो सकता है ! और जहाँ तक बात रही technology की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उदय की पूरी premise is centered around introduction of modern technology जिसमें feeder metering शत-प्रतिशत हो, आगे चलके smart meters हर एक उपभोक्ता के पास लगें और हम isolate कर सकें कि कहाँ पे AT&C losses ज्यादा हैं, और AT&C losses को जितना ज्यादा हम control कर पाते हैं उतना ज्यादा बिजली के दामों को भी हम control कर पाएंगे ! आज भी साधारणता अगर औसतन बिजली का generating cost देखें तो शायद वो Rs 3.5-4.00 से अधिक नहीं है पूरे देश में, गुजरात में उससे भी कम, कुछ में 50 पैसे, 1 रूपया ज्यादा ! पर उसके बावजूद consumer तक पहुँचते पहुचते वो rates prohibitively expensive हो जाते हैं ! तो हमारी कोशिश है कि technology के माध्यम से और आपने बहुत सही फ़रमाया, technology के माध्यम से affordability of power को कैसे रखना और साथ ही साथ जो गलत काम करते हैं उनको bring them to book so that the honest people can get the benefit of cheaper and more affordable power.

Moderator. We will take one question quickly, Mr Sanjeev Bhasin, I think from IIFM, he has a question, yeah please?

Q. Firstly, I will like to congratulate you that your UDAY bonds was a success. And they served almost a four-fold purpose with the utilities, the power finance companies and the producers along with the PSU banks getting a big relief. I stay in Gurgaon and let me be honest about it there has been no power cut now for the last many many months that's a kudos. However, the cost of transmission is extremely expensive, we are paying Rs 8.40 which is the highest price ever in the utility. So my request would be that, you know, in time to come this will become very very inflationary and that is where the whole problem lies which is where we want more action. Firstly we think UDAY has been par excellence, how you got them placed at 7.30+75 basis points and there was apprehension whether it could be placed well-off. So kudos to you for that but if you could have a look into this distribution because in time to come that inflationary trend will actually escalate.

Hon'ble Minister: Sir the entire focus of UDAY is on operational efficiency, financial reengineering was only the first step. So if on a scale of 1-10, I was to give the importance to different elements of UDAY, financial engineering was probably 3 but the operational efficiency and the importance of improving that is probably 8 or 9. So I can reassure you that we are working closely with the states and gradually the states are also realising that the people today have become

very conscious and have become an aspirational class who is demanding better services from their governments. So those governments that do not perform will have to bear the brunt of the people's reaction and action. So I am very confident that in the days to come states also will get equally conscious about improving operational efficiencies.

Q. Can we have a deadline when all government offices because of clean energy would be on solar power, that is one thing. And secondly, I mean that is because you have done what has not been done in 60 years so we hope that this government will do this also and second is the linking of the rivers so that hydro electricity can be properly utilized and when can we have a deadline when the water to Pakistan will stop and we have a hydro power there.

Hon'ble Minister: Well, I can certainly tell you that the deadlines as far as economic projects go cannot be set by the government. I want to make the whole process an economically viable project that everybody is interested in actually implementing in. By giving a deadline sitting here but if it's not economically viable it will never happen so my own whole effort has been to look at economies of scale, expand the infrastructure and the business to such a level that today now government offices will pay Rs 6 or Rs 7 a unit. It's an economically very viable proposition to use solar, having said that, they still need the grid because solar will give you power only in the day. So we are working closely with governments, the Ministry of Urban Development is working closely for all the central government offices, many states have become conscious about it. And I am fairly confident that probably in the next 4 or 5 years we will see that almost across the country we will have a large web of solar installations on government buildings. In fact, you will be happy to know India today has a 300MW solar rooftop base, 300 MW. Our plan is by 2022 to scale it up to 40,000 MW, a 130 times, that is the plan that India and Modi government has set.

Q. That there is, with all the banks, there is a lot of stressed assets especially in the power sector, so I have a suggestion that, you know, if there is a, you know, if there is a committee which can be set up along with the power ministry and the banking because it keeps roaming about with various banks. Because one projects, the projects are so large that not one bank but many banks finance it, it takes a long time. Whereas, many of the assets which have been created they are languishing, they have been completed 20%, 50%, 80%, it's a national waste and almost about a lakh of crore is stuck up in these stuck up power plants so if there is some thought about it…

Hon'ble Minister: Well, it's a good suggestion, in fact, I have been holding meetings even at my level with the bankers on the stressed projects. We have made certain policy interventions already which would help to resolve some of these projects. For example, Teesta, you will be amazed Teesta is a project which was 90% complete in Sikkim, 90% but there were so many contradictions and fights going on between investors, state government, EPC contractor, lenders engineer, so many issues because of which it was stalled when I became a minister. We had a series of meetings in my own office and finally resolved all these fights, the project got back into implementation. And only, day before yesterday I was told that by March that project will be fully operationalised, by December the first units will be operational. So we are working on solving these stressed asset issues, committees cannot solves these problems because committees can look at macro issues, most of these projects have individual problems, some of them have had bad promoter problems. The other day there was a project that State Bank brought up to me, the loans to that project was nearly Rs 4,000 crores, when the project was assessed by NTPC they said we wouldn't buy it for Rs 600 crores, so I don't know where the rest of the money went. The issue is that we will have to look at each project individually and assess what is the real value proposition in that project and what is the future possibility to resolve that problem and get it up with a bow.

Moderator: I think जो सबसे बड़ी चीज़ पीयूष जी ने कही है कि भारत नजदीकी भविष्य में हकीकत में power cut-free nation बनेगा I think ये ही एक सबसे बड़ा vision statement उनकी तरफ से है और बहुत बहुत शुक्रिया सर आप you literally air-dashed to participate in this event, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, thanks for joining us.